यूपी के हाथ से फिसल रहा चीनी का कटोरा

प्रदेश में इस साल 2 लाख हेक्टे. गन्ने के क्षेत्रफल में आई कमी

अभिषेक रंजन। लखनऊ

उप्र में गन्ना किसानों की राजनीति कर कई दलों ने वोट की मोटी फसल काटी लेकिन जब किसानों के भुगतान की बात आई तो सरकार चीनी मिल मालिकों के आगे बेबस साबित हुई। नतीजतन चीनी मिलों और सरकारों के बीच किसान पिसता रहा। हाल यह है कि पश्चिम यूपी जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है वह अब प्रदेश के हाथों से फिसलता जा रहा है। किसानों के गन्ना भुगतान और मिल मालिकों के बीच कोई सामन्जस्य न होने के कारण प्रदेश के किसान अब गन्ना की बुवाई से कतरा रहे है यही कारण है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार यूपी में करीब 9.2 लाख हेक्टेयर गन्ने के क्षेत्रफल में कमी आई है। हालांकि सरकारी आकड़ों पर गौर करें तो इस बार यूपी में गन्ना क्षेत्रफल 2209888 हेक्टेअर है जबकि 2013-14 में यह क्षेत्रफल 2360266 हेक्टअर था स्पष्ट है कि इस बार 1 लाख 50 हजार 378 हेक्टेअर गन्ने के क्षेत्रफल में कमी आई है। वास्तविक आकड़ों पर गौर करे तो यह कमी करीब 2 लाख हेक्टेअर से ज्यादा है। इतना ही नहीं नवंबर से शुरु होने वाले पेराई सत्र में भी गन्ना किसान और मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि गन्ना किसान इस बार 350 रुपए प्रति कुंतल की मांग पर अड़े हैं और मिल मालिक 250 रुपए से ऊपर देने को राजी नहीं है। जाहिर है कि इस बार भी यूपी में गन्ने को लेकर सियासत तेज होगी।

अगर बात की जाए घटते गन्ना क्षेत्रफल की तो भुगतान में देरी और खेत खाली न होने के कारण किसानों की रूचि गन्ने की बुवाई में घटी है। मिलों की अपनी गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर ही रंगराजन कमेटी ने मिलों और गन्ना किसानों के बीच

लिकेंज की बात कही है। इस लिकेंज के तहत गन्ना और चीनी का दाम एक अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। करीब डेढ़ दशक पूर्व भारत में सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में ही पैदा होता था तब चीनी मिलों की संख्या भी अंगुलियों पर गिनी ली जाती थी मगर अब हालात बदल गए हैं। चीनी मिलें तो बढ़ी लेकिन गन्ने की बुवाई के प्रति किसानों की रूचि घटने लगी है। बीते पेराई सत्र 2013-14 में प्रदेश के ऐसे लाखों किसान है जिन्होंने गन्ना तो बेच दिया लेकिन भुगतान समय से न होने पर किसान अपनी बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाए। किसानों का गन्ना तो बिक गया लेकिन फरवरी से लेकर जून माह तक उनका भुगतान नहीं हो पाया इस कारण किसानों के कई महत्वपूर्ण घरेलू कार्य प्रभावित हुए। गन्ना विभाग ने 2013-14 और 2014-15 गन्ना क्षेत्रफल के प्रारम्भिक अनुमान जारी किए उसमें प्रदेश में 6.4 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल घटा है, वास्तविक आंकड़े इससे काफी ज्यादा है। इन आंकड़ों में शामली में 12.2 लाख , मेरठ में 9.8, गाजियाबाद में 10.5, बुलन्दशहर में 19.8, बागपत में 8.3, मुरादाबाद में 7.8, अलीगढ़ में 25.4, बरेली में 13.7, शाहजहांपुर में 17.6, बदायूं में 10, एटा में 19.8, हरदोई में 13.4, बाराबंकी में 13.2, फैजाबाद में 40, वाराणसी में 13.5 हेक्टेअर गन्ने के क्षेत्रफल में कमी आई है। यह तो बानगी भर है अन्य जिलों का भी कमोबेश यही हाल है। मौजूदा समय में राज्य सरकार के ऊपर अभी पांच हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का गन्ना भुगतान बकाया है।

पायनियर 9/9/2014-P-2

Scan!